

# चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वालों को एक करोड़ का मुआवजा मिलें : इलाहाबाद एचसी

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से मारे गए अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजन को मुआवजे की रकम को कम बताया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुआवजे की रकम कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश में महामारी फैलने और क्वारैंटाइन सेंटर्स के हालात को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मारे गए लोगों के परिजन को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, उम्मीद करते हैं कि राज्य चुनाव आयोग और सरकार मुआवजे की रकम पर फिर से विचार करेंगे और अगली सुनवाई पर इस बारे में हमें बताएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने जानबूझकर बिना आरटी-पीसीआर जांच के कर्मचारियों को ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया। ऐसे में परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी का मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए।



**यूपी सरकार ने 30 लाख तय किए थे**

**चुनाव के 'विनाशकारी परिणाम' का अनुमान लगाने में फेल रहे ईसी और सरकार**

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्ती दिखा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के बीच में विधानसभा और पंचायत चुनाव कराने के अपने फैसले को लेकर चुनाव आयोग, उच्च अदालतें और सरकार इसके विनाशकारी नतीजों का अनुमान लगाने में नाकाम रहीं। कोर्ट ने एक केस में विशेष आधार पर गाजियाबाद के एक बिल्डर को जनवरी, 2022 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए यह टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बिल्डर के खिलाफ एक संपत्ति पर कथित कब्जा करने को लेकर केस दर्ज किया है। कोर्ट ने वो विशेष आधार भी बताए, जिनके आधार पर प्रोटेक्शन दी गई। कोर्ट ने कहा कि महामारी जैसे कारणों के चलते मृत्यु की आशंका किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने का आधार बनाई जा सकती है।

# 3 साल के रिजल्ट से होगा 10वीं का वैल्यूएशन

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893232137

एमपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के वैल्यूएशन व एग्जाम के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया गया है। एक-दो दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। इन्हें पिछले तीन साल के रिजल्ट के

**मप्र बोर्ड :** 12वीं की परीक्षा का निर्णय 15 तक

आधार पर अंक दिए जाएंगे। कोई छात्र यदि किसी साल फेल भी हुआ है तो उसे 33 फीसदी अंक देकर पास कर दिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण थमने के बाद होगी। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यह कोरोना की परिस्थिति के अनुसार तय किया जाएगा। राज्यमंत्री इंदर

सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं के स्टूडेंट्स को सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। मार्कशीट में अंक देंगे। उन्होंने कहा कि 10वीं व 12वीं को लेकर 15 मई से पहले आदेश जारी कर दिए जाएंगे। की परीक्षा कोरोना संक्रमण थमने के बाद ही होगी।

# कोरोना से मृत शिक्षकों का अंतिम भुगतान तत्काल करें

## डीपीआईने जिलों से मंगाई मौतों की जानकारी

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना संक्रमण काल में अध्यापकों की मौत के बाद अंतिम भुगतान एवं एन्युटी की कारवाई और जानकारी मुख्यालय भेजने को लेकर जिलों को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरते। अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत

ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी कोरोना महामारी या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है, इनके नामिनी से सभी दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के प्रान खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान तथा नामिनी से एन्युटी परचेस की जानकारी प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाए, ताकि इन्हें शीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके। डीपीआई ने कहा है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हें एम्प्लॉई आई डी आवंटित की जा चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के तहत किया जा रहा है।

# डीपीआई ने सभी जिलों से पूछा कितने अध्यापकों की मौत हुई

➤ अंतिम भुगतान और एन्युटी की कार्रवाई के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ►► भोपाल

लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना संक्रमण काल में अध्यापकों की मृत्यु के बाद अंतिम भुगतान एवं एन्युटी की कार्रवाई और जानकारी मुख्यालय भेजने को लेकर जिलों को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतें। अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कल्यावत ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिनकी कोरोना महामारी या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है।

## यह होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हें एम्प्लॉई आईडी आवंटित की जा चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के तहत किया जा रहा है, उनको कोषालय के माध्यम से अंतिम भुगतान किया जाएगा। साथ ही ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अध्यापक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उन्हें एम्प्लॉई कोड आवंटित नहीं हुआ है, ऐसे अध्यापकों के अंतिम भुगतान की कार्रवाई पैरा 1 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्रवाई से संचालनालय को अवगत कराएं।

# अध्यापकों की मृत्यु उपरांत तत्काल भुगतान के निर्देश जारी

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री किरावत ने निर्देश दिया कि कि वर्तमान में कोरोना होने से संक्रमण का दौर चल रहा है, जिसमें अधिकतर अध्यापकों की कोरोना संबंधी महामारी के कारण मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसलिये निर्देशित किया जाता है कि जिलों के अंतर्गत ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी कोरोना महामारी एवं अन्य कारणों से मृत्यु हो गई है, इनके नामिनी से

समस्त दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के प्रान खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान तथा नामिनी से एन्युटी परचेज की जानकारी प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें ताकि उन्हें शीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके। निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हें एम्प्लॉई आईडी आवंटित की जा

चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है, उनका कोषालय के माध्यम से अंतिम भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अध्यापक जिनकी नियुक्ति की जा चुकी है किन्तु उन्हें एम्प्लॉई कोड आवंटित नहीं हुआ है ऐसे अध्यापकों के अंतिम भुगतान की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत करायें।

# डीपीआई ने जिलों से पूछा, कोरोना संक्रमण से कितने शिक्षकों की हुई मौत

शिक्षक संगठन 5 सौ से अधिक शिक्षकों की मौत का कर रहे दावा

भोपाल ( शप्र )। लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना संक्रमण काल में जिलों से शिक्षकों की मौत की जानकारी मांगी है। जिससे अध्यापकों की मृत्यु के अंतिम भुगतान एवं एन्युटी की कार्रवाई त्वरित की जा सके। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से नहीं करने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों का दावा है कि पांच सौ से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी कोरोना महामारी या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है। इनके नामिनि से सभी दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के प्रान खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान तथा नामिनि से एन्युटी परचेस की जानकारी प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाए, ताकि इन्हें शीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके। आदेश में कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हें एम्प्लॉई आईडी आवंटित की जा चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के तहत किया जा रहा है, उनको कोषालय के माध्यम अंतिम भुगतान किया जाएगा। साथ ही ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अध्यापक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है लेकिन उन्हें एम्प्लॉई कोड आवंटित नहीं हुआ है ऐसे अध्यापकों के अंतिम भुगतान की कार्यवाही पैरा 1 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संक्रमित हुए  
शिक्षकों को इलाज  
के लिए मिले  
विशेष अवकाश  
सुविधा

## बिना आर्डर जारी किए शिक्षकों को कोरोना इयूटी पर बुला रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में अनुविभागीय अधिकारी बिना आर्डर जारी किए शिक्षकों को कोरोना इयूटी पर बुला रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए समग्र शिक्षक संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

बताया गया कि कोरोना संक्रमण के बीच वर्तमान में प्रदेश भर में कोरोना महामारी के बचाव अभियानों में शिक्षकों को बड़ी संख्या में इयूटी पर लगाया गया है। जिनमें रेलवे स्टेशनों चिकित्सालय नगर निगम नगर पालिका टोल नाकों संक्रमित नागरिकों के सर्वे टीकाकरण कोविड सेंटरों सहित अनेक कोविड बचाव से संबंधित अभियानों में शिक्षकों तैनात किया गया है। जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक संक्रमित भी हो रहे हैं। लेकिन कोरोना इयूटी पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में राज्य शासन ने संबंधित शिक्षक- कर्मचारियों को उपचार के लिए विशेष अवकाश का कोई प्रावधान नहीं किया है।

इस संबंध में समग्र शिक्षक संघ ने राज्य शासन को पत्र लिखा है। जिसमें कोविड-19 की इयूटी के दौरान संक्रमित हो रहे शिक्षकों को उस चिकित्सकीय अवधि में उपचार के लिए 30 से 45 दिन दिवस की अवधि का विशेष अवकाश दिए जाने का प्रावधान किए जाने की मांग की है।

### शिक्षकों की इयूटी लगाने की प्रक्रिया में भी हो सुधार

समग्र शिक्षक संघ के महामंत्री संजय तिवारी ने राज्य शासन को लिखे पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि शिक्षकों की अलग-अलग स्तर पर कोरोना बचाव अभियान में सेवाएं तो ली जा रही हैं। लेकिन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित नहीं किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर तो शिक्षकों को मौखिक रूप से कोविड-19 से संबंधित बचाव कार्यों में लगाया जा रहा है। जिस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। मौखिक रूप से कोरोना इयूटी लगाने वाले अधिकारियों पर शासन कार्रवाई करें।

### बिना आर्डर के बुलाया जा रहा है शिक्षकों को

संगठन के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार दुबे का कहना कि कई मामलों में नियमानुसार आर्डर जारी न किए जाने के कारण इयूटी के दौरान अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को शासन स्तर से निर्धारित सहायता मिलने में समस्या आ रही है। वही निर्धारित आदेश के बिना कोरोना इयूटी करने वाले शिक्षक अर्जित अवकाश की पात्रता से भी वंचित हो रहे हैं। उन्होंने राज्य शासन के समक्ष यह भी मांग उठाई कि प्रदेश भर में कोरोना इयूटी में लगे शिक्षकों को इयूटी के एवज में अर्जित अवकाश दिया जाए।

# शिक्षक के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं विरोध में उतरे शिक्षकों ने काली पट्टी बांध किया वैक्सीनेशन केंद्र पर काम

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

वार्ड क्र. 18 के वैक्सीनेशन सेंटर शासकीय नर्सिंग कॉलेज में पदस्थ शिक्षक संदीप बौरासी के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों में आक्रोश है। प्रांतीय शिक्षक संघ के बैनर तले उन्होंने बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन दिया। संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. कैलाश बारोड़ ने बताया आरोपियों के खिलाफ कब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार से वैक्सीनेशन सेंटर, सर्वे में लगे शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उनका कहना है कि शिक्षक शासकीय कार्य कर रहा था। ऐसे में उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी प्रशासन की है।

## हर सेंटर पर सुरक्षा के इंतजाम करवाएं

शिक्षकों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि जहां भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता



काली पट्टी व काला मास्क पहन विरोध जताती एक शिक्षक।

इंतजाम करवाएं, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। अब तक जिले में 70 शिक्षकों का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो चुका है। उनके परिजनों को आर्थिक मदद मिलना तो दूर उन्हें समय पर उपचार तक नहीं दिया जा रहा है।



# छात्रों से वसूली करोड़ों की लेट फीस अब वापस करेंगे विवि



जमा कराएगा। वर्तमान में जिन विवि ने विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस ली है, उन्हें 300 से एक हजार रुपए तक विलंब और विशेष विलंब शुल्क विद्यार्थियों को वापस करना होंगे। इस संबंध में सबसे ज्यादा शिकायतें जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की दर्ज हुई हैं। जबकि चरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने फीस जमा करने की अंतिम तिथि

बीस मई कर रखा है। अब उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीयू को अंतिम तिथि में दस दिन की बढ़ोतरी करना होगी।

**आर्थिक स्थिति हुई खराब:** कोरोना संक्रमण में लगे कोरोना कर्फ्यू ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। ऐसे में छात्रों के माता-पिता फीस जमा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद भी विवि छात्रों से परीक्षा के लिए 300 से 1000 रुपए का अतिरिक्त

शुल्क जमा करा रहे हैं। इससे विवि के खजाने तो भर रहे हैं, लेकिन इसका असर मध्यम और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार पर पड़ रहा है। फीस वापस होने से उन्हें कुछ समय की राहत जरूर मिल सकती है। वहीं हजारों विद्यार्थी जो विलंब शुल्क के अभाव में फीस जमा करने बंचित रह गये हैं, उन्हें भी तीस मई तक फार्म जमा करने का मौका मिल जाएगा।

**भोज में 15 मई से आनलाइन जमा होंगे फार्म:** सूबे के सभी विवि विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से लेंगे। इसके तहत भोज विवि ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षाएं जून के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती हैं। परीक्षाओं में शामिल होने विवि 15 मई से 15 जून तक आनलाइन आवेदन जमा कराएगा। इसके बाद यूजी-पीजी की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कापियां प्रदेश के सभी जिलों के 417 कालेजों में जमा हो सकेंगी। विद्यार्थी 11 रीजनल केंद्रों में भी कापियां जमा कर सकते हैं।

कार्यालय प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की यूजी-पीजी की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से होंगी। ये परीक्षाएं जून और जुलाई में होंगी। इसके बाद भी विश्वविद्यालयों ने अप्रैल और मई में विद्यार्थियों से हजार-हजार रुपए विलंब और विशेष विलंब शुल्क लेकर परीक्षा फार्म जमा कराए हैं। इससे विश्वविद्यालयों के खातों में करोड़ों रुपए जमा हो गये हैं, जो अब उन्हें विद्यार्थियों को वापस करना होंगे। कोरोना संक्रमण में विद्यार्थी और उनके घर परिवार के सदस्य एक-एक रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके बाद भी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों से सामान्य फीस के साथ 300 से एक हजार रुपए तक का विलंब और विशेष विलंब फीस लगाकर परीक्षा फार्म जमा करा लिये हैं। ये व्यवस्था अभी भी जारी है। प्रदेश के कालेजों और विवि में करीब बीस हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किये हैं कि अब कोई भी विवि तीस मई तक बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म

# कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षार्थियों को करना होगा रिजल्ट के घोषणा का इंतजार

30 मई तक घोषित करने के आदेश

भास्कर संवाददाता | रीवा

शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 11 वीं के परीक्षार्थियों को अभी परीक्षा परिणाम की घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए 30 मई तक रिजल्ट घोषित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अब परीक्षार्थियों को 30 मई का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले दिनों कक्षा 9वीं एवं 11वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई थी। इसके लिए विमर्श पोर्टल पर ऑन लाइन रिजल्ट देखने की बात कही गई थी। इसके लिए संबंधित छात्र काफी परेशान रहे। रिजल्ट विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसके कारण परीक्षार्थियों में काफी असंतोष भी देखा गया। इसी बीच अब विभागीय स्तर से नया आदेश जारी किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आगामी 30 मई तक रिजल्ट विधिवत घोषित किया जाएगा।



## आयुक्त ने जारी किया आदेश

बताया गया है कि विगत 10 मई को ही लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आयुक्त द्वारा शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि में आगामी 30 मई तक की वृद्धि की जाती है। परीक्षी संबंधी जानकारी को विमर्श पोर्टल पर 30 मई तक दर्ज किया जाय। उल्लेखनीय है कि इसके पहले कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षा परिणाम 15 मई तक घोषित करने के निर्देश दिए गए थे।

# मालनपुर में सैनिक स्कूल खुलने से विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा भिण्ड

**भिण्ड, ब्यूरो**

मध्यप्रदेश सरकार के सहकारितामंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया एवं सांसद श्रीमती संध्या राय ने संयुक्त रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिण्ड जिले के विधानसभा क्षेत्र गोहद में खोले जा रहे नवीन सैनिक स्कूल के लिए नगर पंचायत मालनपुर में 2095 हेक्टर सरकारी जमीन आवंटन करने का निर्णय लेकर पूर्व में की गई घोषणा को पूरा कर दिया है, जिससे अब भिण्ड जिला विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा।

उन्होंने सैनिक स्कूल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान मालनपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। उस पर अमल करते हुए उन्होंने जमीन का

**सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार**

आवंटन कर प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेज दिया है। यह निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने भिण्ड जिला, गोहद, मालनपुर एवं चंबल सभाग के विद्यार्थियों के लिए विकास की दिशा में कार्य किया है, जिससे सभी विद्यार्थी प्रवेश लेकर योग्य व कर्मठ सैन्य अधिकारी बनकर नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा विकास में

विश्वास रखती है। जनता से वायदा किया था कि सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे। आज पूर्ण रूप से जमीन आवंटन के साथ उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और शीघ्र ही इसका भूमि पूजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल की मांग लंबे समय से की जा रही थी वह अब पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी क्षेत्रीय जनता की मांग पर भिण्ड जिले के मालनपुर में सैनिक स्कूल स्थापित करके विकास को गति प्रदान की है।

## स्कूल बंद, पढ़ाई नहीं...



ये नजारा शहरी छात्र का नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भेड़ाघाट का है। घर के आंगन में बैठकर छात्रा आनलाइन पढ़ाई कर रही है। कोरोनाकाल में अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से आनलाइन कक्षाएं बंद हो गई हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी है। छात्र आनलाइन कोचिंग की क्लास के माध्यम से कोर्स को पूरा कर रहे हैं।

● उमा शंकर मिश्रा

# अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर विवाद, पूर्व पार्षद बोले-मुसलमान हो तो कार्रवाई रोक दो अधिकारी का जवाब 'पहले मैं सरकारी नौकर हूं'

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल  
मो.नं. 9300697983

नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जनप्रतिनिधियों को रास नहीं आ रही। नतीजा अधिकारियों पर दबाव बना रहे है। ऐसा ही एक ऑडियो बुधवार को वायरल हुआ, जिसमें पूर्व पार्षद शाहवर मंसूरी अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान को धमका रहे हैं।

पहले उन्होंने खान को मुसलमान होने का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने को कहा, जब खान ने कहा कि धर्म अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह। वह पहले सरकारी नौकर हैं बाद में मुसलमान। कार्रवाई तो नहीं रुकेगी। इससे पूर्व पार्षद नाराज हो गए और खान के साथ बदतमीजी की। बता दें कि



लॉकडाउन के दौरान नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीमों शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चला रही हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए शहर में जहां भी दुकानें खुल रह हैं। उन्हें सील करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम ने गौतम नगर पुलिस के साथ मिलकर दो दिन पहले खुली सब्जीमंडी को बंद कराया था। कोरोना कर्फ्यू के बाद भी यहां दुकानदार कारोबार करते रहे हैं। इसके चलते नगर निगम के

अतिक्रमण अमले ने मंगलवार को यहां अवैध शेडों को हटाने की कार्रवाई की थी, जो शाहवर मंसूरी को रास नहीं आई और उन्होंने फोन पर निगम अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान को मुसलमान होने का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने को कहा था। नासिर के नाम मानने पर पूर्व पार्षद ने उनसे बदतमीजी भी की थी।

**अतिक्रमण अधिकारी ने लिखी नोटशीट:** अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान को फोन पर धमकाने और कार्रवाई रोकने के मामले ने अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब ने नोटशीट लिख दी है। जिसे विभागीय अपर आयुक्त के मार्फत निगम आयुक्त को भेजा गया है। उम्मीद जताई है कि इस मामले में पूर्व पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

## मंसूरी और नासिर की बातचीत

**मंसूरी:** यार, नासिर भाई, एक बात बताओ... हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। बेचारे मुसलमान कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप भी मुसलमान हो।

**नासिर:** मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मुसलमान भी हूँ।

**मंसूरी:** नहीं-नहीं सरकारी कर्मचारी तो हो। लॉकडाउन से दुकानें खुली नहीं है। आप आ गए और शेड तोड़ने लगे।

**नासिर:** यह टीआई साहब से बोलिए। मंडी करोंद शिफ्ट हो गई है। अभी तो और तोड़ेंगे। हिंदू-मुसलमान वाली बात तो है ही नहीं। हम सरकारी कर्मचारी हैं। आप जो कह रहे हैं... मुसलमान हैं।

**मंसूरी:** आप तो पागल हो।

**नासिर:** आप हिंदू-मुसलमान की बात कर रहे हो। कलेक्टर-कमिश्नर का ऑर्डर है। कलेक्टर-कमिश्नर से बढ़कर हो क्या?

**मंसूरी:** कौन

**नासिर:** आप कह रहे हो न कि मुसलमान हो, बनकर तोड़ रहे हो। मुसलमान और हिंदू कर रहे हो। देखो हमसे बात कायदे में करें। हम आपसे जैसे बात करते हैं, अदब से ही बात करना। पागल-वागल नहीं कहना।

**मंसूरी:** वाकई मैं यार तुम तो पागल हो।

**नासिर:** मैं पागल-वागल नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है।

# यूजी-पीजी स्टूडेंट 31 तक बिना लेट फीस कर सकेंगे आवेदन

## उच्चशिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को दिए निर्देश

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

[editor@peoplessamachar.co.in](mailto:editor@peoplessamachar.co.in)

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की यूजी और पीजी में परीक्षा फार्म नहीं भर पाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे सभी छात्र अब परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके लिए उन्हें लेट फीस भी नहीं देना होगा।

इस बारे में मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यूजी और पीजी के छात्र जो आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनमें से कई छात्र परीक्षा फार्म नहीं भर पाए हैं। लेट फीस

होने के बाद भी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उन्हें हम एक और मौका देने जा रहे हैं। वे सभी छात्र अब 31 मई तक बिना कोई लेट फीस दिए परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इससे सभी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सीमा में परीक्षा कार्यक्रम को लागू करें। उल्लेखनीय है कि यूजी अंतिम वर्ष पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 में घोषित किया जाएगा। पीजी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 आयोजित की जाएंगी।

# सरकारी शिक्षक ने 'सांसों' के लिए 48 घंटे में जुटाए 3 लाख रुपए, पिछोर व खनियाधाना में दिए चार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

पीपुल्स ब्यूरो • शिवपुरी  
मो.नं. 7999881392

समाज में शिक्षक को भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता से लेकर अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले की संज्ञा दी जाती रही है। शिवपुरी जिले के पिछोर के एक छोटे से गांव करारखेड़ा निवासी सरकारी शिक्षक साकेत पुरोहित ने कोरोना संकट के बीच जब पिछोर व खनियाधाना में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था की दरकार महसूस की तो उन्होंने इसके लिए मदद जुटाना शुरू किया। इस सकारात्मक सोच



के साथ साकेत ने क्षेत्र के लोगों की 'सांसों' के लिए सोशल साइट के जरिए अभियान शुरू किया। नतीजा यह रहा कि 48 घंटे में ही पिछोर व खनियाधाना से 2 लाख

98 हजार 620 रुपए एकत्र भी हो गए। इससे पिछोर व खनियाधाना में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराने के अलावा अन्य स्वास्थ्य संबंधी सामग्री खरीदी जाएगी।

## शिवपुरी के मदद बैंक से मिली साकेत को प्रेरणा

साकेत बताते हैं कि उन्हें यह प्रेरणा शिवपुरी में 'मदद बैंक' के प्रमुख सेवादार बृजेश तोमर से मिली है। जिला स्तर पर तो मदद के लिए लगातार 'मदद बैंक' के हाथ आगे बढ़ ही रहे हैं। यही कारण रहा कि साकेत ने अपने अभियान को पिछोर, खनियाधाना तक ही सीमित रखा और वही के लोगों को जोड़कर अपील की। उनकी अपील के बाद से उनके पास लोगों के इस मुहिम में सहयोग करने के लिए लगातार मैसेज और फोन आ रहे हैं।

## नेता, व्यापारी संघ से लेकर शिक्षक संघ आए आगे

साकेत की अपील के बाद हर तबके के लोग आगे आए। पिछोर की भाजपा नेत्री पूनम सोनी (बुआजी) ने 62 हजार रुपए दिए। पिछोर के व्यापारी मंडल ने 60 हजार रुपए की मदद की। राज्य शिक्षक संघ पिछोर ने भी सहयोग किया। शिक्षक साकेत का कहना है कि इस मुहिम की सफलता की खुशी तब और बढ़ गई, जब इसका असर करैरा और खोड़ के लोगों पर भी हुआ। उन्होंने भी वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के लिए राशि जुटाई है।

# 11 जून तक अपलोड करने होंगे 10 वीं के अंक

भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 10वीं के स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। बोर्ड ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 10वीं

क्लास के स्टूडेंट्स को हर विषय के लिए 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। इनमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से दिए जाएंगे और 80 मार्क्स साल भर में आयोजित अलग-अलग परीक्षाओं के आधार पर दिए

जाएंगे। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को 11 जून तक 10वीं कक्षा के छात्रों के अंक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इस साल सीबीएसई 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 20 जून तक जारी करेगा।



# इंडियन आर्मी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कोविड के चलते टला

भोपाल। देश में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा आर्मी सेंटर, हैदराबाद में 30 मई को आयोजित की जानी थी। इस बारे में डिफेंस विंग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि 30 मई को होने वाला इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडीडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट [joinindian-army.nic.in](http://joinindian-army.nic.in) पर विजिट कर सकते हैं। यह परीक्षा 30 मई को जयपुर और जोधपुर में होनी थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई परीक्षाएं टालीं गई हैं।

# एडवाइजरी : वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जी मोबाइल ऐप से बचें

भोपाल। एडीजी राज्य सायबर योगेश चौधरी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए सायबर अपराधी फर्जी मोबाइल ऐप बनाकर लिंक मैसेज से भेज कर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए डाउनलोड करने को कहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन के माध्यम से मेलवेयर हमारे मोबाइल में आ जाते हैं जो कि हमारे मोबाइल सुरक्षा

के लिए घातक होते हैं। जब हम लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को इंस्टाल करते हैं तो वह बहुत सारी परमीशन लेता है जो हम दे देते हैं। फिर वह ऐप असली काम शुरू करती है, वह हमारे पर्सनल फोटोस, वीडियोस सारे कॉन्टैक्ट, एसएमएस, व्हाट्सएप की चेट, मोबाइल में सेव बैंकिंग के पासवर्ड हमारे सारे ईमेल आदि सायबर अपराधियों तक पहुंचा देती है।

# अधिकांश विवि द्वारा अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी यूजीसी ने विवि पर छोड़ा एग्जाम का फैसला

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे प्रकरणों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। विवि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। देश भर के ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। लेकिन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) को यूजीसी गाइडलाइन के साथ प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है। इसके



लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षा गाइडलाइन को आधार बनाया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बीयू ने सभी परीक्षाएं जून-जुलाई में ओपन बुक पैटर्न से कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि यूजीसी गाइडलाइन नहीं आने से असमंजस बना हुआ था। अब यदि प्रदेश सरकार यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आदेश जारी करती है तो फिर बीयू की भी केवल अंतिम वर्ष

और ईयर की परीक्षाएं होंगी। वहीं दूसरी ओर देश के जिन विवि ने अंतिम वर्ष के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रमोशन देने की तैयारी की थी, उनके निर्णय पर अब यूजीसी की मुहर लग गई है। यूजीसी के सचिव डॉ. रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। यूजीसी का कहना है कि संक्रमण का प्रभाव देश में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षा की स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। इस बीच, विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के आंतरिक आंकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है।

## सीबीएसई दोस्त फार लाइफ

सीबीएसई ने विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को देखते हुए "सीबीएसई दोस्त फार लाइफ" एप लांच किया है। इस एप के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए जाएंगे। यह एप विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उन्हें 12वीं के बाद करियर विकल्प से संबंधित सलाह भी देगा।

स्टेट यूनिवर्सिटी होने से यूजीसी के साथ राज्य शासन के आदेश का पालन होता है। हमने प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सभी कक्षाओं के ओपन बुक एग्जाम कराने की तैयारी कर ली है। अब यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार के जो भी आदेश होंगे, उनका पालन किया जाएगा। डॉ. एचएस त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू, भोपाल

# एनटीए ने बढ़ाई होटल मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा की तारीख

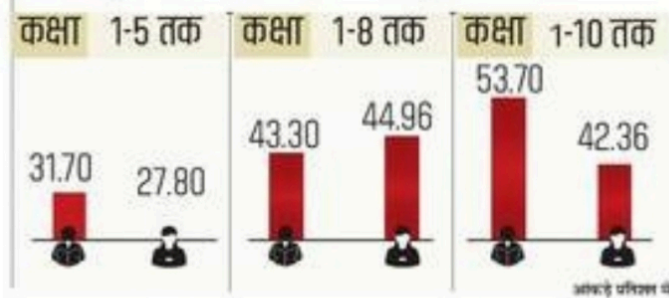
भोपाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने होटल मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए आयोजित एंट्रेंस एग्जाम में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 12 जून कर दी गई है। कोविड के चलते स्टूडेंट्स के लिए यह सुविधा दी गई है क्योंकि कई कारणों से स्टूडेंट्स इस समय आवेदन नहीं कर पा रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को बताया गया है कि वे अपने फॉर्म में 2 से 8 जून तक करेक्शन कर सकेंगे। इस प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कुल 200 सवाल होते हैं।

# सरकार ने स्कूल छोड़ने संबंधी योजना का बजट 90% से भी ज्यादा कम किया गांवों में बच्चे 10वीं से पहले छोड़ रहे स्कूल

इंदौर/ भोपाल | DBStar

प्रदेश के शहरी इलाकों में भले ही स्कूलों की चकाचौंध बनी हुई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात इसके उलट हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 42% बच्चे 10वीं में पहुंचने से पहले ही स्कूल से तौबा कर लेते हैं। सरकारी आंकड़ों में ही यह सच्चाई सामने आई है। बावजूद इसके सरकार ने इन बच्चों के स्कूल छोड़ने संबंधी योजना का बजट 90% से भी ज्यादा कम कर दिया। प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों में आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कक्षा पहली से 5वीं के 31% से ज्यादा बालक और 27% से ज्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। मिडिल स्कूल में यह आंकड़ा करीब 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा केंद्र के अलावा राज्य सरकार ने भी छात्रवृत्ति का सालाना बजट आधा कर दिया है। 2019-20 में 11वीं-12वीं व कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना में 30700 लाख रुपए का प्रावधान था। जिसे 2020-21 में घटाकर 17,250 लाख रुपए कर दिया गया।

## लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा



## एक्सपर्ट व्यू

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की जरूरत के अनुसार पाठ्य-सामग्री का न होना, प्रशासन की दुविधा के कारण उत्तरदायित्व हीनता का होना और बच्चों के लिए जरूरी गतिविधियों का समय पर न हो पाना इसकी खास वजह है।

**डॉ. दामोदर, पूर्व सदस्य, एनसीईआरटी**

15 साल में स्कूलों की बिल्डिंग बढ़ती गई, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। आदिवासी विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच तालमेल का अभाव होने से भी इस पर बहुत असर हुआ है।

**रमाकांत पांडे, शैक्षणिक मामलों के जानकार**

**रजिस्ट्रेशन** की अंतिम तारीख 17 मई

## जेएलयू की प्रवेश परीक्षा 22 को, 25 मई को आणा रिजल्ट

भोपाल। जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, मध्य भारत की सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा जेएलयूईटी (जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) 22 मई को आयोजित की जाएगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और यह अनिश्चित है कि कब परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसलिए हायर एजुकेशन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, जेएलयू ने प्रवेश परीक्षा का फिर से शुरू किया है और जेएलयूईटी के माध्यम से होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 17 मई है और परीक्षा के परिणाम 25 मई को घोषित किए जाएंगे। यह दो भागों में होगी, पहला भाग जेएलयूईटी के कुल अंकों में 60 % का योगदान देगा। वहीं, दूसरा भाग जेएलयूईटी के 40% का योगदान देगा। अंतिम स्कोर दोनों अंकों का योग होगा। जेएलयू के वाइस चांसलर डॉ. संदीप शास्त्री ने कहा कि जैसा कि कहा गया है कि सफलता उन लोगों को मिलती है, जो जल्दी शुरूआत करते हैं।

31 मई तक कैसे जमा  
होंगे परीक्षा फार्म

# शिक्षा मंत्री के ट्वीट के बाद राडुविवि में बढ़ी हलचल

हरिद्वार, जबलपुर।

परीक्षाएं कब से होंगी इसके लेकर अब संशय बरकरार है। परीक्षार्थी से लेकर कुलपति कोई भी निश्चित तारीख नहीं बता पा रहा है। इसी बीच प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के सोशल मीडिया पर वायरल किए गए एक संदेश ने विश्वविद्यालयों में हड़कंप मचा दिया है। शिक्षा मंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि 31 मई तक एग्जाम फार्म जमा करने वाले विद्यार्थियों से कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय के

## विश्वविद्यालय में हलचल तेज

उच्च शिक्षा विभाग से मिले दिशेष के उपरंत विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी चिंतित है क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिलों में कोरोना जलता कर्फू लगा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जबलपुर में 17 मई तक

अलावा प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी तक एग्जाम डेट ही घोषित नहीं की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर

कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के फार्म 31 मई तक बिना विलंब शुल्क के भरे जा सकेंगे। यह संदेश पढ़ते ही सबसे पहले विद्यार्थी के जेहन में एक ही सवाल आया कि



कोरोना जलता कर्फू लगा हुआ है। वहीं कुछ माह में संक्रमण की स्थिति क्या रहेगी। इसके लेकर भी असमंजस है। हालांकि राबो दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन की खात करे तो उनका दावा है कि परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हैं। उन्हें ओपन बुक परीक्षाएं फिजिले सत्र में भी कराई थीं, लिहाजा पूर्व का अनुभव काम आएगा।

क्या परीक्षा फार्म जमा हो रहे हैं। बस फिर क्या था, विद्यार्थियों ने पतासाजी शुरू कर दी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क साधने लगे, लेकिन किसी को कोई

सकारात्मक जवाब नहीं मिला। क्योंकि विश्वविद्यालयों में लॉक डाउन के चलते मार्च से ही कामकाज पूरी तरह ठप है।

उल्लेखनीय है कि कोविड -19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया था कि स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर, द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति की जाएंगी। उक्त निर्णय के तहत ही उच्च शिक्षा ने ओपन बुक परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एक निर्देश जारी किया है।

जिसके तहत 4 मई को जारी एक आदेश में कहा गया था कि स्नातक अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएंगी तथा परीक्षा परिणाम जुलाई में घोषित किया जाएगा। इसी तरह स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 में आयोजित की जाएंगी तथा परीक्षा परिणाम अगस्त 2021 में घोषित किया जाएगा। वहीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शेष प्रयोग एक परीक्षाएं ओपन बुक परीक्षा की समाप्ति के बाद आयोजित की जाएंगी।

# ओपन बुक परीक्षा का फार्म भरने 30 मई तक का वक्त, यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में जून से आयोजित परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की तिथि 30 मई तय हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कई यूनिवर्सिटी ने इसके बाद परीक्षा के आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से इस मामले को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं विद्यार्थी अपने सत्र को समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञात हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 30 मई तक सभी स्नातक और स्नातकोत्तर



परीक्षाओं के परीक्षा फार्म भरवाने की व्यवस्था दी है। यूनिवर्सिटी को इस संबंध में लिंक खोलनी है ताकि जून से परीक्षा प्रारंभ हो सके। इस बार कोरोना महामारी में ओपन बुक एग्जाम होना है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इसी तरह से परीक्षा में शामिल किया जाना है लेकिन अभी

तक इसकी कोई कार्य योजना नहीं तय हो पाई है। विभाग ने शजारीरिक दूरी के साथ ज्यादा से ज्यादा केंद्रों में परीक्षा कपियों का संग्रह करने की व्यवस्था करने को कहा है। **लाकडाउन से हो रही देरी :** कुलसचिव प्रो. एनसी पेंडसे ने कहा कि लाकडाउन की वजह से प्रशासन कोई निर्णय नहीं कर रहा है। परीक्षा आवेदन भरवाने के लिए कियोस्क खुलना चाहिए। लाकडाउन में एमपी आलनाइन के सारे कियोस्क बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी होगी। वहीं अन्य यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को मोबाइल, कम्प्यूटर के जरिए घर बैठे ही परीक्षा आवेदन भरने के लिए कहा है ताकि कोरोना संक्रमण न फैल सके।



# पेंशन कार्यालय में अफसरों ने रोका 15 कर्मियों का भुगतान, एक की मौत

पैसे के अभाव में उपचार न कराने पर दो की हालत बनी हुई है गंभीर

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

कोषालय से लेकर पेंशन कार्यालय तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिस्टम को निगल रहा है। ताजा मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है। जहां पर अनुरक्षण खंड एवं परियोजना क्रमांक 1 के दिसंबर में 15 कर्मचारी रिटायर हुए थे लेकिन आज तक इनका पेंशन भुगतान नहीं किया गया है।

जबकि इन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के 1 महीने पहले नवंबर 2020 में पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कंप्लेंट प्रकरण कोषालय को भिजवाया था। यहां का अनुमोदन होने के उपरांत पेंशन कार्यालय को यह भुगतान करना था। दुर्भाग्य देखें कि पूरे 5 महीने निकल चुके हैं। रिटायरमेंट होने के बाद इन गरीब कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले एक कर्मचारी बीमार हुआ। पैसे के अभाव में वह समय से उपचार नहीं करवा पाया और उसकी मौत हो गई। इस कर्मचारी का नाम भगवानदास मालवीय बताया जा रहा है। जबकि पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे राजेंद्र कुमार तिवारी एवं देवीदास की हालत गंभीर बनी हुई है। यह दोनों कर्मचारी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष डीके गौर का कहना है कि इस संबंध में पूरी समस्या से

## कोविड-19 नियमों का पालन न करने के कारण सिंधु मेडिकल स्टोर बैरागढ़ को किया सील

भोपाल। कोविड-19 गाइड लाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं अन्य शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर केएल अग्रवाल, बैरागढ़ तहसीलदार गुलाब सिंह, इंस्पेक्टर रवीन्द्र, विभूति नारायण और पुलिस बल की उपस्थिति में भोपाल बैरागढ़ स्थित सिंधु मेडिकल स्टोर पर छापा मार कार्यवाही करते हुए संबंधित दुकान संचालक को नोटिस जारी कर दुकान को सील कर दिया गया है। दुकान को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद किया गया है। दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसके बाद नियमानुसार लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।



कलेक्टर को भी अवगत करा दिया गया है लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया है कि पैसे के अभाव में ही एक कर्मचारी की मौत हुई है। इस मामले में पेंशन कार्यालय की संभागीय अधिकारी यशोदा चौहान एवं कोषालय अधिकारी केके शर्मा से दो बार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन इन दोनों ही अधिकारियों ने मोबाइल पर बात करना उचित नहीं समझा।

## कार्यालयों में अधिकारियों की बिगड़ी आदतें

वरिष्ठ कर्मचारी नेता प्रमोद कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि कोषालय और पेंशन

कार्यालयों में अधिकारियों की आदतें शासकीय सेवकों द्वारा ही बिगाड़ दी गई है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जल्दी काम कराने के चक्कर में कुछ कर्मचारी स्वयं रिश्तत का ऑफर देते हैं। जिसका खामियाजा पूरे कर्मचारी जगत को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भुगतान क्यों रोका गया है। सरकार को इस मामले की तत्काल जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को कठोर दंड देना चाहिए। उनका का यह भी आरोप है कि कोषालय और पेंशन कार्यालयों में सालों से भ्रष्ट अधिकारी जमे हुए हैं। जिसके कारण निर्दोष कर्मचारियों को अपना ही भुगतान लेने के लिए चप्पल रगडनी पड़ रही है।

## विश्वविद्यालय ने बढ़ाई परीक्षा फार्म भरने की तिथि

का.प्र.। रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथि बढ़ा दी है। विवि द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा तिथि के अनुसार अब द्वितीय, चतुर्थ और छठवें सेमेस्टर के परीक्षार्थी आगामी 30 मई तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म भर सकेंगे। विवि से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में संबंधित सेमेस्टर में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथि 15 मई तय की गई थी। लेकिन कोरोना इफेक्ट और लॉकडाउन को देखते हुए विवि प्रबंधन ने तिथि में बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 30 मई कर दिया है।

इसके अलावा दूरवर्ती के अंतर्गत विभिन्न कोर्स में अध्ययनरत ऐसे परीक्षार्थी जिनके परीक्षा फार्म भरने की तिथि 15 मई थी वह भी अब आगामी 30 मई तक परीक्षा फार्म भर सकेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण कियोस्क सेंटर न खुले होने के कारण छात्रों के सामने परीक्षा फार्म भरने की समस्या मौजूद है। आगामी 17 मई तक जिले में टोटल लॉकडाउन है। संभावना जताई जा रही है कि कोरोना इफेक्ट को देखते हुए लॉकडाउन अवधि को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

# परीक्षा की तैयारी में जरूरी है लिखने का अभ्यास करना

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। कोविड के कारण पूरा साल विद्यार्थियों ने आनलाइन पढ़ाई की। इस पढ़ाई में शिक्षकों ने आनलाइन ही विषय को समझाया और विद्यार्थियों ने आनलाइन ही बातों को समझा। इस प्रक्रिया में बच्चों का लिखने का अभ्यास पूरी तरह छूट गया है। जबकि जो परीक्षा होती है उसमें तीन घंटों तक विद्यार्थी को सिर्फ लिखना ही होता है। बाकी सारी कक्षाओं की परीक्षा तो हो चुकी हैं। दसवीं के बच्चों को असिसमेन्ट के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि परीक्षाएं होना भी हैं या नहीं। होंगी भी तो कब होंगी। इस असमंजस की स्थिति के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही लिखने का अभ्यास भी।

काउंसलर वर्षा चौहान ने बताया कि आनलाइन पढ़ाई से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। एक विद्यार्थी के रूप में जो आदतें होनी थीं वो छूट गई है। इस समय जो परीक्षा की तैयारी चल भी रही है उनमें विद्यार्थी पढ़-पढ़ कर थक चुके हैं। तो अब पढ़ाई के तरीके में थोड़ा बदलाव करते हुए लिखने का अभ्यास करें। न सिर्फ लिखने का बल्कि लगातार तीन घंटे टेबल- कुर्सी पर बैठ कर लिखने का



## आनलाइन पढ़ाई होने पर विद्यार्थियों की छूट गई लिखने की आदत

अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इस समय लिखने की आदत छूटी होने से बच्चों को परीक्षा देने में लगातार बैठने और लिखने में ही सबसे ज्यादा परेशानी होगी। वैसे भी कहा जाता है कि परीक्षा लिखने की होती है। जिसने जितना अच्छा पेपर लिखा नंबर उसी के आधार पर मिलते हैं। अब जब सारी जानकारी होने पर भी बच्चे परीक्षा में लिख भी नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ाई का क्या अर्थ। इसलिए अब समय है कि बच्चे लिख कर रिवीजन करें। तभी इस समय का सदुपयोग हो सकेगा और परीक्षा में इसका लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थी प्राची ठाकुर ने बताया कि वे हर दिन एक घंटा लिखने का अभ्यास कर रही हैं। जिससे परीक्षा में परेशानी न हो। और लिख कर पढ़ने से पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद भी रहता है।

# उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ा दी आवेदन की तिथि, इससे बीयू में बढ़ सकते हैं प्राइवेट परीक्षार्थी प्रथम वर्ष में साढ़े 12 हजार, दूसरे और तीसरे में करीब 30 हजार विद्यार्थियों ने किए हैं आवेदन

हरिमूमि न्यूज ॥ मोपाल

ओपन बुक सिस्टम से आयोजित होने वाली बीयू की प्रथम वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक करीब साढ़े 12 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं दूसरे और तीसरे वर्ष में करीब 30 हजार प्राइवेट विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किए गए हैं। हालांकि अब उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन की तारीख 31 मई कर दी है। इसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने संभावना जताई जा रही है।

दरअसल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय अपनी सभी परीक्षाएं इस बार ओपन बुक सिस्टम से लेगा। प्राइवेट परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ ओपन बुक सिस्टम से ही कराई जाएंगी। प्रथम से तीसरे वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में करीब 42 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। बीयू 225 केंद्रों पर यूजी-पीजी की परीक्षाओं की कॉपियां जमा कराएगा। नोडल कॉलेज प्रोफेसर्स की टीम बनाकर उक्त कॉलेजों से कॉपियां अपने पास बुलाएगा। इसके बाद बीयू अपने गोपनीय वाहन से मूल्यांकन कराने लेकर आएगा। बीयू की सीमाओं से बाहर रहने वाले विद्यार्थी उपकुलसचिव के नाम से डाक के माध्यम से कॉपियों को बीयू भेज सकते हैं।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय अपनी सभी परीक्षाएं इस बार ओपन बुक सिस्टम से लेगा, प्राइवेट परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ ओपन बुक सिस्टम से ही कराई जाएंगी। प्रथम से तीसरे वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में करीब 42 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे

## 20 मई तक का दिया गया था समय



बीते दिनों ही बीयू द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की संशोधित तारीख जारी की गई है। इसके अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, होमसाइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम आनर्स के विद्यार्थियों के लिए बीस मई तक फॉर्म जमा करने का समय दिया गया था। वहीं एक हजार रुपये विशेष विलंब शुल्क के साथ 21 मई तक का समय दिया गया था। अब विभाग की ओर से इस संबंध में आवेदन की तारीख बढ़ाने का निर्णय होने के बाद तारीख बढ़ाई जाएगी।

## जून-जुलाई में होंगी परीक्षाएं

प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए यूजी-पीजी की परीक्षाएं जून और जुलाई में आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के तहत आयोजित होगी। यूजी फाइनाल ईयर और पीजी फाइनाल ईयर के चौथे सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जून 2021 में आयोजित होगी। इसका परिणाम जुलाई में घोषित होगा। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष, और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के परिणाम अगस्त में घोषित किए जाएंगे। इन छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षा के बाद आयोजित की जाएंगी।

## डिहर, यूजीसी ने परीक्षाओं का फैसला कॉलेजों पर छोड़ा

कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे प्रकरणों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ा है। ऐसे में अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को छोड़ परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है। लेकिन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) को यूजीसी गाइडलाइन के साथ प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बीयू ने अपनी सभी परीक्षाएं जून-जुलाई में ओपन बुक पैटर्न पर करने की आदेश जारी कर दिए हैं। बीयू के रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी का कहना है कि यह स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहां यूजीसी की गाइडलाइन के साथ राज्य शासन के आदेश का पालन किया जाता है। हमने प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सभी कक्षाओं के ओपन बुक परीक्षाएं करने की तैयारी कर ली है। अब यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार के जो भी आदेश होंगे, उनका पालन किया जाएगा।

# लाकडाउन के दौरान बच्चों को व्यस्त रखने अभिभावक अपना रहे कई तरीके

घर में बनाई खेलने की जगह, नए-नए खिलौनों का बच्चे ले रहे आनंद

**जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)।** लाकडाउन के दौरान अगर किसी को सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, तो वे हैं बच्चे। बच्चों को जरा भी समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें? कहां जाएं? किससे मिले, किसके साथ खेलें। ये सारे सवाल हर रोज बच्चों को परेशान कर रहे हैं। बच्चों को खुश करने के लिए अभिभावक उनके लिए आनलाइन विभिन्न खिलौनों की खरीदारी कर रहे हैं ताकि बच्चा उनके साथ घर पर ही व्यस्त रहे और उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने की कमी न खले। अभिभावकों की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के लिए एक खुशनुमा माहौल बना रहे हैं। बच्चे इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं।



## घर के एक कमरे को बना दिया

**प्ले ग्राउंड :** कुंतल मालवीय ने बताया कि उनका बेटा कुश तीन साल का है। पिछले साल से आए कोरोना के कारण उसका बाहर जाकर खेलना बंद करा दिया था। सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के बाद ही जब हालात सामान्य हुए तब उसने बाहर खेलना शुरू किया था। एक बार फिर से वही स्थिति बनी हुई है। इसके लिए अब घर में एक कमरे को प्ले ग्राउंड की तरह

अभिभावक बच्चों के लिए घर पर कर रहे खेलने की व्यवस्था।

बना दिया है। जहां पर कुश के लिए ढेर सारे खिलौने हैं। कुश इन्हीं से खेलता है और खुश रहता है। खुश रहने से बच्चा स्वस्थ भी रहता है। कमरे में उसके लिए स्लाइड, एयर वैग चेर, क्लिक बोर्ड, स्केटिंग आदि शामिल किए हैं। जिनसे वो हर समय खेलता है।

**बच्चों के खेलने के लिए बनाई जगह :** बच्चों को खेलने के लिए स्पेस

चाहिए। घर में सामान होने के कारण सामान टूटने का डर रहता है। यह कहना है कि विभा सिंह का। इन्होंने बताया कि घर के काफी सामान को पैग करके रख दिया है ताकि बच्चों को खेलने के लिए अच्छा स्पेस मिल सके। इस दौरान वे लुका छिपी के साथ ही की इनडोर खेल खेलते हैं। इससे मोबाइल से भी दूरी बनी रहती है और वे खुश भी रहते हैं।

# पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार

जबलपुर (नप्र)। मप्र सरकार पर कर्मचारियों के साथ छलावे का आरोप मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लगाया है। उन्होंने कहा कि चार फीसद अंशदान नहीं बल्कि पुरानी पेंशन बहाल करने के आदेश जारी होनी चाहिए। ये अध्यापकों के साथ छलावा है। अध्यापक प्रकोष्ठ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों अध्यापकों तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के लगभग पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना में शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत किया गया है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा अपने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत का अंशदान कई वर्ष पूर्व से ही दिया जा रहा है।

# सीबीएसई दोस्त फॉर

## लाइफ एप लांच

भोपाल। कोरोना संक्रमण काल में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को देखते हुए सीबीएसई ने सीबीएसई दोस्त फार लाइफ एप लांच किया है। इस एप के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए जाएंगे। यह एप विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उन्हें 12वीं के बाद करियर विकल्प से संबंधित सलाह भी देगा।

# बीआरसीसी कार्यालय में भड़की आग

सतना | रामनगर कस्बे में रीवा रोड पर संचालित बीआरसीसी कार्यालय में बुधवार सुबह शार्ट-सर्किट से आग लग गई, जिससे 2 कम्प्यूटर समेत जरूरी दस्तावेज खाक हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीआरसीसी धरणीश द्विवेदी पारिवारिक कारणों से अवकाश पर हैं, जिसके कारण उनके कक्ष के बाहर ताला लगा हुआ था, मगर अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर आ रहे थे। हमेशा की तरह 12 मई को भी कार्यालय में काम चल रहा था, तभी लगभग 11 बजे बीआरसीसी कक्ष से धुंआ उठने लगा, यह देखकर कर्मचारियों ने फौरन प्रभारी कक्ष का ताला खोला तो देखा कि शार्ट-सर्किट के कारण तारों से होते हुए आग ने वहां रखे 2 कम्प्यूटर, सीपीयू और दस्तावेजों को चपेट में ले लिया है। फौरन ही डॉयल 100 और फायर ब्रिगेड को फोन कर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई, लगभग एक घंटे तक जूझने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। आगजनी की शिकायत रामनगर थाने में दर्ज कराई गई है, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह खबर दे दी गई है।



# 145 छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल देरी से एडमीशन लेने के कारण बनी स्थिति

कार्यालय प्रतिनिधि | रीवा

जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत 145 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रथम वर्ष में एडमीशन लेने वाले इन छात्रों का अभी तक न तो परीक्षा फार्म ही भराया गया और न ही परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार का निर्देश हायर एजुकेशन और विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की उपेक्षा के कारण इन छात्रों का क्या होगा इसका पता आने वाले समय में ही चल पाएगा।

## आखिर कहां है समस्या

बताया गया है कि हायर एजुकेशन द्वारा प्रथम वर्ष में एडमीशन लेने वाले विद्यार्थियों को अंतिम मौका देते हुए 15 अप्रैल तिथि तय की थी। विभागीय सूत्रों की माने तो अंतिम तिथि तक 145 विद्यार्थियों ने अपने दस्तावेज जमा कर विभिन्न महाविद्यालयों में एडमीशन लिया। अब देरी से एडमीशन लेने के कारण इन संबंधित विद्यार्थियों के सामने समस्या यह है कि उनकी परीक्षा कब होगी। क्योंकि अभी तक इनका नामांकन तक नहीं हुआ है। गौरतलब है कि हायर एजुकेशन द्वारा अक्टूबर माह से अप्रैल माह के अंतराल में आठ बार एडमीशन लेने की तिथि में बढ़ोत्तरी की गई थी।

## असमंजस में महाविद्यालय प्रबंधन



देरी से एडमीशन लेने वाले छात्रों की परीक्षा तब तक नहीं कराई जा सकती जब तक कि वह प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म नहीं भर देते। मार्च माह तक में जिन छात्रों ने प्रथम वर्ष में एडमीशन ले लिया था। उनका परीक्षा फार्म भरा कर उनकी परीक्षा भी संपन्न कराई जा चुकी है। गत

दिवस उनका रिजल्ट भी घोषित हो गया है। अब जिन छात्रों ने देरी से प्रथम वर्ष में एडमीशन लिया है उनके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। यहां तक कि नामांकन फार्म तक नहीं भराया गया है। इन छात्रों की परीक्षा कब होगी इसे लेकर महाविद्यालय प्रबंधन के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

## इनका कहना है

जिन विद्यार्थियों ने देरी से प्रथम वर्ष में एडमीशन लिया है उनका अभी नामांकन फार्म भी नहीं भराया गया है। देरी से एडमीशन होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। हायर एजुकेशन से इस संबंध में गाइडलाइन मांगा जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने समय से एडमीशन प्रोसेस को पूरा कर लिया था उनकी परीक्षा हो गई। अधिकतर विद्यार्थियों का रिजल्ट भी घोषित हो गया।

**प्रो. पंकज श्रीवास्तव**, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा

# ओपन बुक प्रणाली से होंगी महाविद्यालयीन परीक्षाएं

सतना। स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से आयोजित की जाएगी। स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून में आयोजित होगी और जुलाई में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी तथा परीक्षा परिणाम अगस्त में घोषित किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय वेबसाइट पर पेपर अपलोड करेगा। पेपर अपलोड होने के बाद विद्यार्थियों को कॉपियां घर पर लिखनी होंगी और कलेक्शन सेंटर पर कापी जमा करनी होगी।

# विवि को 30 तक बढ़ानी होगी परीक्षा फार्म भरने की तिथि

अभी 15 तक  
तय रहा समय,  
यूजी-पीजी के  
छात्रों को राहत

जागरण, रीवा

वार्षिक पाठ्यक्रम  
नियमित स्नातक-  
स्नातकोत्तर कक्षाओं के  
छात्र अब 30 मई तक  
ऑनलाइन परीक्षा फार्म



भर सकेंगे। ऐसे ही अन्य स्नातकोत्तर, स्नातक सेमेस्टर पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु भी 30 मई तक परीक्षा फार्म का पोर्टल खुला रहेगा। इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है। विभाग ने सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने के लिए कहा है। रीवा, शहडोल सम्भाग समेत प्रदेशभर में लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू के चलते विभाग ने यह निर्णय लिया है।

विदित हो कि मार्च 2021 में होने वाली स्नातक प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय विगत 5 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरवा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि विश्वविद्यालय ने बढ़ाकर 15 मई निर्धारित की है। ऐसे

ही स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के परीक्षा फार्म भी विश्वविद्यालय द्वारा 10 मई तक बिना विलम्ब शुल्क के भराये गए हैं। अब इन सभी कक्षाओं के छात्रों को 31 मई तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की मोहलत मिलेगी। उक्त दिनांक तक परीक्षा फार्म भरने में छात्रों को किसी तरह की विलम्ब शुल्क नहीं लगेगी।

## सेमेस्टर परीक्षा के फार्म भी जारी

इधर, विश्वविद्यालय ने जून 2021 में होने वाली नियमित सेमेस्टर परीक्षाओं के फार्म भी जारी कर दिए हैं। स्नातक दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें और दसवें सेमेस्टर के छात्र 15 मई से ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकेंगे।

## अगले माह होनी है परीक्षा

गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली के तहत कराने हेतु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है। विभाग के संशोधित आदेशानुसार स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून में होगी, जिसका परिणाम विश्वविद्यालय को जुलाई में घोषित करना होगा। इसी प्रकार स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष, तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई माह में होगी, जिसका परिणाम अगस्त में जारी किया जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा तथा असाइमेंट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। जबकि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के रिजल्ट में प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, असाइमेंट सहित प्रथम वर्ष में प्राप्त अंक के परिणाम को भी जोड़ा जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष की तरह ही तृतीय वर्ष के छात्रों का भी परिणाम तैयार होगा। इस परिप्रेक्ष्य में ही विश्वविद्यालय द्वारा विगत मार्च महीने से परीक्षा फार्म भराये जा रहे हैं।

परीक्षा फार्म भरने के लिए अंतिम तिथि 30 मई विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। इसी अवधि में स्नातकोत्तर द्वितीय, चतुर्थ व षष्ठम् सेमेस्टर के छात्रों को भी परीक्षा फार्म भरना होगा। इस प्रक्रिया में ऑनर्स बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र शामिल होंगे। साथ ही बीसीए, बीबीए, एलएलबी, बीपीएड, बीएएलएलबी, बीएसडब्ल्यू सहित अन्य सेमेस्टर पद्धति के स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र सम्मिलित होंगे। ऐसे ही स्नातकोत्तर एमएसडब्ल्यू, एमसीए, एलएलएम, एमबीए, एमए, एमएससी के छात्रों को भी ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरना होगा।

## बीएड, एमएड के परीक्षा फार्म भी 15 से

इसके अलावा विश्वविद्यालय ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड, एमएड, एमलिव के परीक्षा फार्म भी जारी कर दिए हैं। नियमित बीएड, एमएड व एमलिव के छात्र 15 से 30 मई के बीच ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इसके उपरांत 6 जून तक विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने का समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। बता दें कि इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा भी विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक प्रणाली के तहत ही आयोजित कराई जायेगी।

# विद्यालय अभी नहीं भरेंगे ओएमआर शीट्स

## माशिमं ने प्रक्रिया पर लगाई रोक, पृथक से जारी की जायेगी सूचना

जागरण, रीवा। जिले के विद्यालय कक्षा 10वीं की आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षाओं की ओएमआर शीट्स अभी नहीं भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने इस कार्यवाही को अभी रोके रखने के लिए आदेशित किया है। उक्त प्रक्रिया शुरू करने व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा कराने माशिमं द्वारा पृथक से सूचना जारी की जायेगी। गौरतलब है कि जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् 10वीं, 12वीं के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बाबत माशिमं ने गत 7 मई को आदेश प्रसारित कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अब स्थगित परीक्षा कराने हेतु आगामी तिथि माशिमं द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के चलते माशिमं ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि सत्र 2020-21 की मुख्य बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी माशिमं कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाया है। जबकि



10वीं, 12वीं की मुख्य प्रायोगिक परीक्षा गत 17 अप्रैल से माशिमं के निर्देश पर अब तक चलती रहीं। हालांकि उक्त परीक्षा के तहत छात्रों को उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए थे और 20 मई तक छात्रों को विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी थी। वहीं,

स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ ही केंद्र में होनी थी। बहरहाल, अब माशिमं ने उक्त गतिविधि को भी रोक दिया है। माशिमं द्वारा उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने या प्रायोगिक परीक्षा बाबत अन्य किसी निर्णय से बाद में अवगत कराया जायेगा। बता दें कि इस प्रक्रिया में जिले के 539 सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र शामिल हो रहे हैं। 10वीं, 12वीं के इन छात्रों की परीक्षा पूर्व के तय कार्यक्रम अनुसार मार्च महीने में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए माशिमं निरंतर परीक्षा कार्यक्रम टालता जा रहा है। अब जून महीने में भी उक्त परीक्षाओं का होना मुश्किल लग रहा है।

**नवोदय विद्यालय में 6वीं में एडमिशन की प्रोसेस फिर रुकी**  
लेक सिटी रिपोर्टर। नवोदय विद्यालय समिति ने 6वीं में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 16 मई से 19 जून तक आयोजित होने वाली थी। 6वीं क्लास में एडमिशन के लिए होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा अभी सिर्फ मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में आयोजित की जाएगी। इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। परीक्षा का नया शेड्यूल चयन परीक्षा की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले जारी किया जाएगा।

# एसबीआई में क्लर्क के 5237 पदों पर भर्ती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में क्लर्क के 5237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। एसबीआई की इस बंपर भर्ती की प्रक्रिया अगले सप्ताह बंद हो जाएगी। ऐसे में एसबीआई में जूनियर एसोसिएट, जेए पदों की भर्ती में अभी आवेदन के लिए एक सप्ताह का मौका है। इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी एसबीआई की वेबसाइट [sbi.co.in](http://sbi.co.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एसबीआई ने 27 अप्रैल 2021 को आवेदन प्रक्रिया की थी और आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2021 है। एसबीआई भर्ती 2021 में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पहले एसबीआई की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा। एसबीआई भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार एक अभ्यर्थी एक ही राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए आवेदन करें उन्हें उस राज्य की भाषा लिखनी और बोलना आती हो।

**महत्वपूर्ण तिथियां:** 26 मई 2021 को प्री-एग्जाम ट्रेनिंग कॉल लेटर, प्रारंभिक परीक्षा जून 21, मुख्य परीक्षा 31 जुलाई, 2021

**शैक्षिक योग्यता:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं।

**आयु सीमा:** 20 वर्ष से 28 वर्ष।

## नेशनल वॉटर डेवलपमेंट में 62 पदों पर भर्ती

नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी (NWD) ने LDC, UDC समेत 62 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 10 मई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएंगे।

**पदों की संख्या - 62 पद:** जूनियर इंजीनियर 16, हिंदी अनुवादक 01, जूनियर लेखा अधिकारी 05, अपर डिवीजन क्लर्क 12, आशुलिपिक 05, लोअर डिवीजन क्लर्क 23।

**योग्यता:** इन पदों के लिए आवेदन करने कैंडिडेट्स 12th पास, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर होने चाहिए।

**आयु सीमा:** इन पदों के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए।

**जरूरी तारीखें:** आवेदन शुरू होने की तारीख- 10 मई आवेदन की आखिरी तारीख- 25 मई

**सिलेक्शन प्रोसेस:** इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (एडवेंस), स्किल टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

**सैलरी:** सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 19,900 - 1,12,400 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।

**एप्लीकेशन फीस:** Gen/OBC- 840 रुपए  
SC/ST/PWD/Women- 500 रुपए

### ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।